

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1185
उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

निजी और सरकारी स्कूलों का डिजिटल रूप से उन्नयन

1185. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:
श्री ओमप्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) क्या सरकार का देश के सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में निजी और सरकारी स्कूलों का डिजिटल रूप से उन्नयन करने का वचार है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;
- (ग) क्या वर्तमान में देश भर के स्कूलों में एनएसएस कार्यक्रमों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है;
- (घ) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है और उक्त डिजिटलीकरण कब तक पूरा होने की संभावना है;
- (ङ.) देश में वर्तमान में इको-क्लब पोर्टल का उपयोग करने वाले स्कूलों की संख्या कतनी है और इसमें भागीदारी के तत्संबंधी राज्य-वार और विशेषकर परभणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जिला-वार आंकड़े क्या हैं; और
- (च) देश में वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए आईसीटी स्मार्ट कक्षाओं के लिए राज्य-वार और महाराष्ट्र के लिए जिला-वार कतनी निधि जारी की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है और अधिकांश सरकारी स्कूल राज्य सरकार और उसके निकायों के प्रशासन के अधीन हैं। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने दिनांक 29.07.2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) को 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति के रूप में घोषित किया, जिसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को समाधान करना है। शिक्षा मंत्रालय देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी और डिजिटल पहल कार्यान्वित करता है। इस पहल का उद्देश्य हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टैबलेट, लैपटॉप और प्रशिक्षण संसाधनों सहित शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में

प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके, डिजिटल बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनलों की सहायता करके शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत, वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में प्रस्तुत राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए निधि प्रदान की जाती है।

शिक्षा मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी और स्मार्ट क्लासरूम के लिए राशि को अनुमोदन देता है। सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम से परिपूर्ण करने के लिए, दिनांक 28 मई, 2025 को एक पूरक परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक आयोजित की गई थी। देश भर में 1,56,213 आईसीटी प्रयोगशालाओं और 1,46,040 स्मार्ट क्लासरूम के अनुमोदन के अलावा, समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी प्रयोगशालाओं के लिए 911.13 करोड़ रुपये और स्मार्ट क्लासरूम के लिए 630.38 करोड़ रुपये के वित्तीय अनुमोदन के साथ कुल 20,456 आईसीटी प्रयोगशालाओं और 29,896 स्मार्ट क्लासरूम को अनुमोदन दिया गया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य के लिए माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए 839 आईसीटी प्रयोगशालाएं और 851 स्मार्ट क्लासरूम अनुमोदित किए गए थे।

वर्तमान वर्ष 2024-25 के दौरान, आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट क्लासरूम के लिए क्रमशः 54,372 लाख रुपये और 59,519 लाख रुपये के वित्तीय आवंटन और वर्ष 2025-26 में क्रमशः 1,59,607 लाख रुपये और 99,697 लाख रुपये के वित्तीय आवंटन को अनुमोदन दिया गया।

महाराष्ट्र राज्य के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 (केजीबीवी सहित) में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम के लिए क्रमशः 1,552.9 लाख रुपये और 50.4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम के लिए क्रमशः 4,517.3 लाख रुपये और 5,911.2 लाख रुपये अनुमोदित किए गए थे।

इको-क्लब पोर्टल (<https://ecoclubs.education.gov.in/>) का उपयोग देश भर के 9,47,851 स्कूलों द्वारा किया जा रहा है। परभणी जिले के कुल 1,544 स्कूल वर्तमान में पंजीकृत हैं और इको-क्लब पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमओवाईएंडएस) के अधीन है। एनएसएस के तहत गतिविधियों को माई भारत पोर्टल (<https://mybharat.gov.in/>) के माध्यम से उत्तरोत्तर डिजिटल किया जा रहा है, जो डिजिटल रूप से एनएसएस स्वयंसेवकों सहित युवाओं के लिए एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है।
